"Knowledge Scholar"
An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research
Volume: 07, Issue: 06, Nov. – Dec. 2020 eISSN NO. 2394-5362
Impact Factor (SJIF) – 5.266

राजसमंद जिले में कॉलेज शिक्षा की स्थितिः एक अध्ययन

डॉ. सर्वेश कुमार

सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान,

राजकीय कन्या महाविद्यालय,

राजसमंद (राज.)

सारांश

राजसमंद, राजस्थान के मेवाड़ अंचल का एक जिला है। जिले में नौ राजकीय महाविद्यालय हैं। अध्ययन में इन्हीं नौ राजकीय महाविद्यालयों में मानवीय और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता व क्रियाशीलता के साथ–साथ शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन का आंकलन किया गया है। तथ्य संकलन में अधिकांशतया प्राथमिक स्रोतों का सहारा लिया गया है। संस्था प्रधानों ने सूचना देते वक्त द्वितीयक स्रोतों का सहारा भी लिया है। शोध का उद्देश्य जिले की कॉलेज शिक्षा में व्याप्त कमियों और उपलब्धियों को चिह्नित करना है, ताकि कमियों में सुधार लाया जासके और अच्छाइयों को अधिक पभावी बनाया जा सके। विश्लेषण में सामने आया है कि गुणात्मक उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में मानवीय और भौतिक संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति के साथ–साथ पाठ्यक्रम में समय सापेक्ष बदलाव करना होगा। संकाय विकास और ऑनलाईन टिचिंग की दिशा में भी पर्याप्त ध्यान देना होगा।

बीज शब्दः मानवीय व भौतिक संसाधन, गुणात्मक उच्च शिक्षा, संकाय विकास।

वर्ष 1991 में राजस्थान के उदयपुर जिले के उत्तरी पूर्वी हिस्से को अलग कर राजसमंद का गठन किया गया। उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद प्राचीन मेवाड़ रियासत का हिस्सा रहे हैं। मेवाड़ का अपना गौरवशाली इतिहास है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, राजसमंद की स्थिति बहुत खुबसूरत नहीं है। यहाँ समग्र साक्षरता दर तो 63.1 प्रतिशत है किंतु महिला साक्षरता दर 48 प्रतिशत से भी नीचे है, जो भयावह तस्वीर दिखाती है। यह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके शैक्षिक पिछड़ेपन के अपने सामाजिक–सांस्कृतिक कारण तो है हीं, किंतु राजकीय प्रयासों के क्रियान्वयन में कमी भी कम उत्तरदायी नहीं है। स्कूली शिक्षा में भी राजसमंद की गिनती राजस्थान के कम नामांकन और उच्च ड्रॉप आऊट रेट वाले जिलों में होती है। कॉलेज शिक्षा की स्थिति भी स्कूली शिक्षा से बहुत भिन्न नहीं है। नाथद्वारा, कन्या नाथद्वारा, राजसमंद, कन्या राजसमंद, रेलमगरा, कुंभलगढ़, आमेट, देवगढ़ और भीम, जिले के नौ राजकीय महाविद्यालय हैं। जिनमें से दो महाविद्यालय महिला शिक्षा को समर्पित हैं। हमने अपने अध्ययन में इन्हीं नौ महाविद्यालयों के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के साथ–साथ शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक गतिविधियों में निष्पादन ;च्मतवितउंदबमद्ध को शामिल किया है।

शोध प्रविधि

तथ्य संकलन में अवलोकन, साक्षात्कार और अनुसूची प्रविधि का प्रयोग किया गया है। शोध के उद्देश्यों से जुड़ी एक अनुसूची विद्यार्थियों के लिए और दूसरी संस्था प्रधानों के लिए तैयार की गई। स्नातक महाविद्यालयों से एक सौ और परास्नातक महाविद्यालयों से एक सौ पचास अनुसूचियाँ भरी गई हैं। महाविद्यालयों के निरीक्षण और अवलोकन के जरिए भी वस्तुस्थिति को समझा गया है। संस्था प्रधानों ने कुछ प्रश्नों के उत्तर में द्वितीयक स्रोतों का सहारा भी लिया है तथ्य संकलन की समयावधि 15 जनवरी, 2020 से 15 मार्च, 2020 है।

उद्देश्य

हमारे शोध का उद्देश्य राजसमंद जिले में कॉलेज शिक्षा में व्याप्त कमियों और अच्छाइयों को चिह्नित करना है, ताकि कमियों को सुधारा जा सके और अच्छाइयों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। सभी विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना समाज और सरकार का प्राथमिक दायित्व है।

जिले में कॉलेज शिक्षा की स्थिति के प्रभावी और वास्तविक अध्ययन के लिए कुछ मापक निर्धारित किए जिनको ध्यान में रखते हुए तथ्यों का संकलन और विश्लेषण किया गया है।

मानव संसाधन की उपलब्धता

जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों में मानव संसाधन की स्थिति चिंताजनक है। सभी महाविद्यालयों में प्राचार्य का पद रिक्त है और वरिष्ठ आचार्य यह पद देख रहे हैं। यह स्थिति केवल राजसमंद की ही नहीं है, अपितु पूरे राजस्थान की भी कमोबेश यही स्थिति है। राज्य में 290 राजकीय महाविद्यालय हैं जिनमें महज 21 महाविद्यालयों में प्राचार्य हैं। राज्य भर में प्राचार्य के 93 प्रतिशत पद खाली हैं। प्राचार्य पद के लिए डिपीसी वर्षों से अटकी हुई है। यही स्थिति टिचिंग स्टाफ की है। राज्य में कॉलेज शिक्षक के 6940 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 4542 शिक्षक ही कार्यरत हैं। इस तरह टिचिंग स्टॉफ में 35 प्रतिशत पद अभी भी रिक्त हैं। पिछले एक दशक में कॉलेज शिक्षकों की केवल दो भर्तियाँ ही पूरी हुई हैं। जहाँ तक राजसमंद की बात है, यहाँ सभी महाविद्यालयों को मिलाकर टिचिंग स्टॉफ के कुल 139 पद स्वीकृत हैं, जिन पर केवल 98 शिक्षक कार्यरत हैं। जिले में टिचिंग स्टॉफ के 30 प्रतिशत पद रिक्त हैं। रिक्त पदों में उन शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है, जो कार्यव्यवस्थार्थ जिले के बाहर के महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। यही स्थिति मंत्रालय स्टॉफ की है। जिले में मंत्रालय स्टॉफ के कुल 149 स्वीकृत पदों में से 87 पद रिक्त हैं। केवल 41 प्रतिशत पदों पर ही मंत्रालयी कार्मिक कार्यरत हैं। जिले के महाविद्यालयों में मानव संसाधन की स्थिति को निम्नांकित रेखाचित्र से समझ सकते हैं।

रिक्त पदों की स्थिति

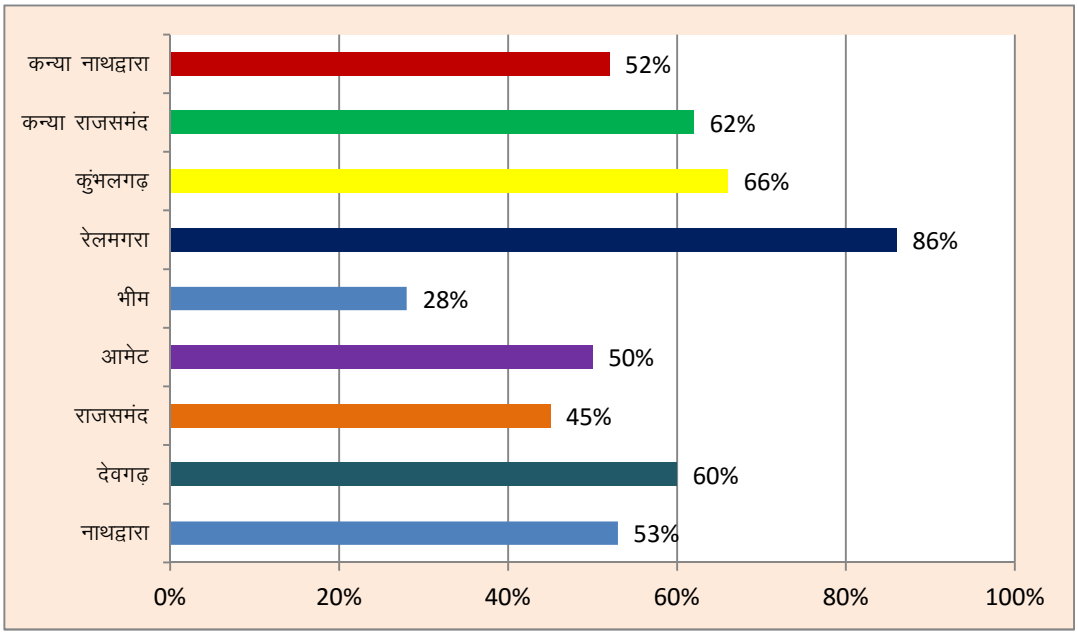

रेखाचित्र से यह स्पष्ट होता है कि मानव संसाधन की सबसे बेहतर स्थिति भीम कॉलेज में है जहाँ केवल 28 प्रतिशत पद रिक्त हैं। सबसे प्रतिकूल स्थिति रेलमगरा कॉलेज की है जहाँ 86 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

भौतिक संसाधनों की उपलब्धता

गौरतलब है कि किसी भी संस्थान में मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन परस्पर पूरक हैं। अकेले मानवीय और भौतिक संसाधन फलदायी नहीं होते हैं। यही स्थिति राजसमंद जिले के महाविद्यालयों की है। कुछ राजकीय महाविद्यालयों में तो मानवीय और भौतिक संसाधन दोनों का अभाव है। कुछ कॉलेजों में भौतिक संसाधन तो हैं, किन्तु मानवीय संसाधन की अल्पता है। जिले के महाविद्यालयों में औसत 8 कक्षा–कक्ष हैं। जबकि अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 6499 है। कुंभलगढ़ कॉलेज 3 कक्षा–कक्ष के साथ चल रहा है। कुछ इसी तरह के हालात कन्या राजसमंद कॉलेज के हैं, जहाँ 4 कक्षा–कक्ष की उपलब्ध है। कॉलेजों में ई–टिचिंग और ई–लर्निंग को संभव बनाने के लिए सरकार ने जहाँ प्रत्येक कॉलेज भवन को ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा है और कॉलेज में स्मार्ट कक्ष व आईसीटी लैब का निर्माण किया है। किंतु ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों में तकनीकी सहायक की अनुपलब्धता के कारण इनका प्रभावी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कॉलेज शिक्षा में तकनीकी सहायक का कोई पद नहीं है। कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर विकास समिति के अनुमोदन से कम्प्यूटर सहायक की अस्थाई नियुक्ति करता है। सरकारी निर्देशानुसार कम्प्यूटर सहायक का अधिकतम मानदेय सात हजार रखा गया है। इतने कम मासिक मानदेय पर एक कुशल तकनीकी सहायक को रख पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि जिले के पचास प्रतिशत से अधिक कॉलेज बिना कम्प्यूटर सहायक के चल रहे हैं, और जहाँ कम्प्यूटर सहायक हैं, वे नाम के कुशल हैं। अब हम बात करते हैं छात्रावास की। जिले में तीन महाविद्यालयों के पास अपने छात्रावास हैं नोडल कॉलेज राजसमंद और भीम कॉलेज के पास जहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, वहीं नाथद्वारा कॉलेज के पास बॉयज हॉस्टल है। दुर्भाग्य से तीनों ही छात्रावास सक्रिय नहीं है। यहाँ कोई विद्यार्थी नहीं रहता। जहाँ तक महाविद्यालयों में पेयजल

और शौचालय की बात है। जिले के सभी महाविद्यालयों में वाटरकूलर और आरओ युक्त पेयजल व्यवस्था है। मूत्रालय की स्थिति लगभग सभी कॉलेजों में बेहतर है। सबसे बेहतर स्थिति भीम कॉलेज की है, जहाँ प्रति 33 विद्यार्थियों पर यूरीनल है। सबसे खराब स्थिति कन्या राजसमंद की है, जहाँ प्रति 110 छात्राओं पर 1 यूरीनल की व्यवसथा है। जिले के सभी महाविद्यालयों ने ग्रीन कैम्पस के लक्ष्य को काफी हद तक हासिल किया है। वृक्षारोपण और स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर एनर्जी की दिशा में प्रगति उल्लेखनीय है।

अकादमिक गुणवत्ता का स्तर

भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभी भी एक सपना है। भारतीय समाज विज्ञान शोध परिषद् ;प्ैब्द्ध की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 83 प्रतिशत शिक्षित युवा रोजगार के काबिल ही नहीं हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली युवाओं में कुशलता, तर्कशीलता और आत्मविश्वास का विकास नहीं कर पा रही है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ज्ञानार्जन की बजाय परीक्षालय की भूमिका अधिक निभा रहे हैं। डिग्री में नियमित विद्यार्थी जरूर दर्शाया जाता है, किंतु हकीकत में 75 प्रतिशत उपस्थिति देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अल्प होती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् ;छ।।ब्द्ध ने अपनी रिपोर्ट में देश के 90 प्रतिशत कॉलेज और 70 प्रतिशत विश्वविद्यालयों को बहुत कमजोर श्रेणी ;टमतल च्ववतद्ध में रखा है। जब देशभर की उच्च शिक्षा सवालों के घेरे में है तब राजस्थान और राजसमंद की स्थिति अलग कैसे हो सकती है। सत्र 2018–19 की बात करें तो जिले के राजकीय महाविद्यालयों का सकल परिणाम 84 प्रतिशत के करीब रहा है, किंतु परिणाम में गुणवत्ता की जाँच में यह स्थिति कमजोर होने लगती है। प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 17 रह जाता है। पचहत्तर प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 प्रतिशत से भी कम हैं यद्यपि अंक किसी की योग्यता का प्रभावी पैमाना नहीं है। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है पाठ्यक्रम का पिछड़ापन। यों तो विश्वविद्यालय समय–समय पर पाठ्यक्रम में बदलाव करता रहता है किंतु यह बदलाव देशकाल में हो रहे बदलाव को साथ लेकर चलने वाला नहीं है। अभी भी पाठ्यक्रम वक्त से बहुत पीछे है। यह समस्या केवल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की ही नहीं है। अभी भी पाठ्यक्रम वक्त से बहुत पीछे है। यह समस्या केवल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की ही नहीं है अपितु भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय अपने पिछड़े पाठ्यक्रम के साथ चल रहे हैं। यही वजह है कि जब दुनिया की श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी होती है, तब भारत का कोई विश्वविद्यालय दूर–दूर तक नजर नहीं आता। संकाय और विषयों की सीमितता अकादमिक स्तर पर एक अन्य चुनौती है। कुछ सीमित विषयों के साथ स्नातक स्तर पर कला संकाय सभी महाविद्यालयों में है, किंतु वाणिज्य और कला संकाय केवल 33 प्रतिशत महाविद्यालयों में है। परास्नातक स्तर तक की पढ़ाई केवल तीन कॉलेज, नाथद्वारा, कन्या नाथद्वारा और राजसमंद में होती है। जहाँ तक क्लास रूम टीचिंग की बात है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय और विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय कई तरह के नवाचार अपना रहे हैं, मसलन छात्र–छात्राओं का ई–कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। खास तौर पर उन विषयों के ई–कंटेंट निर्माण और प्रसार पर अधिक बल दिया जा रहा है, जिन विषयों में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। कॉलेज प्रशासन अपने यू–ट्यूब चैनल और वाट्सअप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों तक ई–कंटेंट पहुँचा रहा है। ऑन लाईन टिचिंग की भी अपनी सीमाएँ हैं। अरावली पर्वतमाला का सघन विस्तार होने के कारण जिले के ग्रामीण

क्षेत्रों में इंटरनेट की पर्याप्त पहुँच नहीं बन पाती है। दूसरा यह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ छात्र–छात्राओं के लिए स्मार्टफोन और महंगे इंटरनेट पैक को खरीद पाना आसान नहीं है। ऑन लाईन टिचिंग में दिव्यांग बच्चों के लिए कोई विशेष उपाय नहीं अपनाए जा रहे हैं। अध्ययन में 64 प्रतिशत विद्यार्थियों ने माना की ऑन लाईन टिचिंग का लाभ उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। कॉलेजों में यू–ट्यूब चैनल्स पर सब्सक्राइबर की अल्प संख्या भी विद्यार्थियों की बात को प्रमाणित करती है। जिले के किसी भी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को 25 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। जिला संसाधन सहायता समिति के जरिए भी शिक्षण व्यवस्था को दुरूस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस समिति का प्रमुख जिले के नोडल कॉलेज का प्राचार्य होता है। नोडल कॉलेज प्राचार्य को यह दायित्व दिया गया है कि वह जिले के किसी भी कॉलेज के किसी शिक्षक को अध्यापन के लिए जिले के जरूरतमंद कॉलेज में अधिकतम 6 दिन के लिए भेजे। ऐसा बार–बार किया जा सकता है। जिले में अमानवीय और भौतिक संसाधनों के समावेशी नियोजन की यह योजना सुन्दर है, किंतु क्रियान्वयन के स्तर पर कुछ विसंगतियाँ सामने आ रही हैं, मसलन छः दिन के अध्यापन में शिक्षक पाठ्यक्रम को पूरा कैसे कर सकता है। इसलिए कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक विषय की सतही चर्चा में ही छः कार्य दिवस पूरे कर जाते हैं। इससे अध्यापन में निरंतरता नहीं बन पाती है। क्लास रूप टिचिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर ने शिक्षक के अध्यापन के लिए प्रतिमाह का लक्ष्य तय कर दिया है, अर्थात् शिक्षक किस माह में पाठ्यक्रम के कितने हिस्से को पढ़ायेगा, यह आयुक्तालय से निर्देशित होता है। प्रत्येक माह के अंत में मासिक टेस्ट का आयोजन होता है। वर्ष भर पहले जब टेस्ट का आरंभ हुआ, तब विद्यार्थियों ने काफी रूचि के साथ भाग लिया था। किंतु धीरे–धीरे छात्र–छात्राएँ मासिक टैस्ट से किनारा करते चले गए। विद्यार्थियों ने बताया कि अध्यापक मासिक टैस्ट के अंक ही नहीं बताते हैं। अधिकांश महाविद्यालयों में अध्यापकों ने मासिक टेस्ट की उत्तर पुस्तिका जाँचना ही जरूरी नहीं समझा। यद्यपि जागरूक विद्यार्थियों ने मासिक टेस्ट का लाभ लेकर स्वयं की अकादमिक गुणवत्ता को सुधारा है। इस तरह अकादमिक गुणवत्ता के लिए कई तरह के नवाचार अपनाए जा रहे हैं, किंतु मानवीय संसाधनों की उपलब्धता के बिना नवाचारों की प्रभावशीलता संदिग्ध है।

पुस्तकालय और वाचनालय

पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, और पुस्तकालय किसी भी शिक्षण संस्थान की आत्मा होता है। नीरवता में अध्ययन करते पाठक, किसी पुस्तकालय की शान होते हैं। पुस्तकालय की पुस्तकें जब पाठकों के इंतजार में धूल फांकने लगें, तो समझा जाना चाहिए कि अध्ययन संस्थान का भविष्य संकट में है। जिले के प्रत्येक कॉलेज का अपना पुस्तकालय है, जिसमें हजारों की संख्या में पुस्तकें हैं। पाठकों के लिए कम–से–कम दो अखबार तो हर कॉलेज में आते हैं। वाचनालय में मैगजींस और जर्नल्स भी आते हैं। पुस्तकालय के विकास के लिए कम्युनिटी बुक बैंक योजना को भी अमल में लाया जा रहा है। जिसमें समाज के गणमान्य लोग कॉलेज पुस्तकालय में पुस्तक दान कर रहे हैं। गत सत्र से संचालित इस योजना के द्वारा जिले के महाविद्यालयों 1373 लोग कॉलेज प्राप्त हुई हैं और आगे भी इस दिशा में प्रयास जारी हैं। पुस्तकालय की स्थिति को हम निम्नलिखित सारणी से समझ सकते हैं–

सारणी 1.1

पुस्तकालय का विस्तार

क्र.सं.	कॉलेज का नाम	पुस्तक संख्या	जर्नल्स	अखबार
1.	नाथद्वारा	24,000	17	4
2.	कन्या नाथद्वारा	8500	12	3
3.	राजसमंद	12411	13	4
4.	कन्या राजसमंद	560	6	3
5.	रेलमगरा	400	4	2
6.	आमेट	4300	7	4
7.	भीम	2670	6	3
8.	देवगढ़	670	4	3
9.	कुंभलगढ़	300	3	2

सर्वाधिक पुस्तकें नाथद्वारा कॉलेज में है, वहीं सबसे कम पुस्तकें कुंभलगढ़ और रेलमगरा कॉलेज में हैं। दोनों ही महाविद्यालय नवीन हैं। प्रत्येक महाविद्यालय ब्रॉड इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ हुआ है, किंतु डिजिटल लाईब्रेरी की सुविधा जिले के किसी भी महाविद्यालय में नहीं है। लाइब्रेरी स्टॉफ का अभाव एक अन्य साझी समस्या है। जिले के सभी महाविद्यालयों को जोड़कर लाइब्रेरी स्टॉफ के कुल 18 पद स्वीकृत हैं, नोडल कॉलेज राजसमंद के अलावा जिले के किसी भी महाविद्यालय में लाइब्रेरी स्टॉफ नहीं है। राजसमंद जिले में एकमात्र पुस्तकालय अध्यक्ष नोडल कॉलेज रामसमंद में हैं। यह स्थिति केवल राजसमंद की ही नहीं है, अपितु राज्य की भी कमोबेश यही स्थिति है। पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती अंतिम बार वर्ष 1991 में निकली थी। पिछले तीन दशक से राज्य सरकार ने कॉलेज जाइब्रेरीयन पद के लिए आवेदन ही नहीं मांगे हैं। राज्य में कॉलेज शिक्षा के अन्तर्गत केवल 43 पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यरत् हैं, इनमें भी अधिकांश लाइब्रेरियन वर्ष 2010 में अनुदानित कॉलेजों को सरकार द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया से आए हैं। इन सभी परिस्थितियों की वजह से पुस्तकालय की उपयोगिता गिरती जा रही है। पुस्तकालयों के ताले लगे हैं और किताबें धूल फांक रही हैं। अध्ययन में 58 प्रतिशत के करीब विद्यार्थियों ने माना कि उन्होंने एक बार भी कॉलेज पुस्तकालय का उपयोग नहीं किया है।

खेल–कूद का ढाँचा और गतिविधि

कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क वाले लोग एक आदर्श समाज का निर्माण करते हैं। अतः खेल का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है अपितु एक खूबसूरत समाज के निर्माण में भी खेलों का योगदान है। यही वजह है कि विद्यालयी स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न खेल–कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। कॉलेज शिक्षा में खेल–कूद की दो अहम् प्रतियोगिताएँ होती हैं। पहला, यूनिवर्सिटी टूर्नामेन्ट और दूसरा अर्जुन दृष्टि खेलकूद प्रतियोगिता। अर्जुन दृष्टि खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर के निर्देशानुसार राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालय में होता है, वहीं

यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का आयोजन एक विश्वविद्यालय अपने से जुड़े सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों के सहयोग से करता है। सत्र 2019–20 में जिले के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् 5 महिला खिलाड़ी और 11 पुरूष खिलाड़ियों ने खो–खो, तैराकी तिरंदाजी, बैडमिंटन, कबड्डी और एथलेटिक्स में अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया। इसी सत्र में अर्जुन दृष्टि खेलकूद प्रतियोगिता के अन्तर्गत 21 खेल गतिविधियों का आयोजन कराया गया था, जिसमें जिले के 25 से अधिक प्रतिभागियों ने 8 खेलों में राज्य स्तर तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। राजसमंद जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने से यहाँ के युवाओं में परंपरागत खेलों के प्रति गहरी रूचि है। स्पोर्ट्स की व्यापक संभावना होने के बावजूद भी युवाओं के लिए खेल का आधाररभूत ढाँचा कमतर है। कुंभलगढ़ और नोडल कॉलेज राजसमंद के पास खेल मैदान तो है, किंतु मैदान पथरीला होने के कारण उपयोगी नहीं है। यद्यपि पथरीले मैदान को भी कामयाब बनाया जा सकता है। जिन महाविद्यालयों के पास खेल मैदान हैं वह चुनिंदा खेलों के लिए ही पर्याप्त है। अभी भी ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का अभाव है, जहाँ अधिकांश खेलों का अभ्यास संभव हो। जिले के किसी भी कॉलेज में शारीरिक शिक्षक का न होना भी एक बड़ी विडम्बना है। सभी महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत तो है, किंतु वर्षों से पद रिक्त चल रहे हैं। यही स्थिति पूरे राज्य के महाविद्यालयों की हैं शारीरिक शिक्षक के लिए अंतिम बार भर्ती वर्ष 1979 में निकली थी। पिछले 41 वर्षों से कॉलेज शारीरिक शिक्षक के लिए आवेदन ही नहीं मांगे गए। राज्य के 300 महाविद्यालयों में से केवल 35 महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं। जिले के सभी महाविद्यालयों में टीचिंग स्टॉफ से किसी सदस्य को खेल का प्रभार दिया गया है। गैर–विशेषज्ञ अधिकारी को खेल प्रभार दिए जाने से खिलाड़ियों को विशेष मदद नहीं मिल पाती है। अध्ययन में सामने आया है कि जो खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने निजी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और कोच का सहारा भी लिया है।

प्रमुख योजनाएँ और उनका क्रियान्वयन

गुणात्मक और रोजगारपरक शिक्षा के साथ–साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कॉलेज शिक्षा में कई योजनाएँ चल रही हैं। हमने कुछ महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को अपने अध्ययन में शामिल किया है, जो निम्नवत् हैं–

1. प्रतियोगिता दक्षता क्लासेज–इस नवाचार का उद्देश्य कॉलेज में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को अकादमिक पढ़ाई के साथ–साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना है। आई.ए.एस., आर.ए.एस., बैंकिंग, शिक्षक, नेट, रेलवे, एस.एस.सी. आदि सेवाओं के लिए तैयारी करवायी जा रही है। इस योजना को कोचिंग संस्थाओं के विकल्प के रूप में लागू किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों द्वारा महंगी कोचिंग ले पाना आसान नहीं है। इसी तरह लैंगिक भेदभाव से ग्रस्त समाज में छात्राओं को कोचिंग मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह के भेदभाव से संरक्षण के लिए दक्षता क्लासेज प्रारंभ की गई हैं। कॉलेज समय सारणी में दक्षता क्लासेज के लिए अलग से कालांश तय किए गए हैं। क्लासेज के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक कॉलेज में नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अध्ययन में सामने आया है कि यह स्कीम

काफी कारगर रही हैं। जिन महाविद्यालयों में सभी संकाय और शिक्षक हैं, वहाँ प्रतियोगिता दक्षता क्लासेज अधिक प्रभावी रही हैं।

2. आनन्दम् प्रोजेक्ट–यह कॉलेज और तकनीकी शिक्षा में संचालित बहुत रूचिकर प्रोजेक्ट है। आनंदम् का उद्देश्य विद्यार्थियों को परोपकार और सामुदायिक सेवा से जोड़ना है। प्रत्येक महाविद्यालय में आनंदम् नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आनंदम् प्रोजेक्ट के अन्तर्गत दो प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित होती हैं–एक व्यक्तिगत कार्य और दूसरा समूहगत कार्य। व्यक्तिगत कार्य में छात्र आनंदम् डायरी का प्रतिदिन लेखन करते हैं। हर दिन किए गए परोपकार को छात्र डायरी में लिखते हैं। मसलन–पक्षियों को दाना खिलाया, किसी गरीब बच्चे की मदद की, पेड़ में पानी दिया, वृद्धजन की सेवा की आदि। समूहगत कार्य में कक्षा के समस्त विद्यार्थियों को 7–8 लोगों के कई समूह में बांट दिया जाता है। प्रत्येक समूह किसी प्रोजेक्ट का चयन करता है और फिर उस पर कार्य करता है। मसलन–सामाजिक वानिकी, सार्वजनिक स्थलों की साफ–सफाई करना, महिला सशक्तिकरण, वाटर हार्वेस्टिंग, नशाखोरी के विरूद्ध जागरूकता, प्लास्टिक की रोकथाम के लिए अभियान आदि। प्रतिदिन 45 मिनट का एक कालांश आनंदम् का होता है, जिसमें विद्यार्थी अपनी डायरी में लिखी नेकी को पढ़कर सुनाते हैं। शिक्षक प्रतिदिन विद्यार्थियों की डायरी की जाँच करते हैं। इस कार्यक्रम का ध्येय छात्र–छात्राओं को सृजन के सुख से जोड़ना है।
3. मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास योजना–राजस्थान कौशल एवं आजीविकास विकास निगम और कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना में कुल 39 प्रकार के रोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मसलन–शेयर बाजार कौशल, योगा प्रशिक्षण कौशल, फिटनेस ट्रेनर स्किल, फैशन डिजाइनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, डाटा एन्ट्री स्किल आदि। प्रत्येक कोर्स में बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से शामिल है। प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढाँचा महाविद्यालय उपलब्ध करा रहा है और प्रशिक्षक की व्यवस्था राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के द्वारा की जा रही है। जिले के सभी महाविद्यालयों में यह कार्यक्रम चल रहा है। सत्र 2019–20 में 13 कोर्सेज में 683 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
4. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)–'मैं नहीं, आप' की थीम पर आधारित यह योजना बहुत समय से कॉलेज शिक्षा में संचालित है। राज्य के अधिकांश महाविद्यालयों में एन.एस.एस. की युनिट गठित की गई है। शहर के कुछ बड़े महाविद्यालयों में दो या इससे अधिक युनिट भी हैं। एक युनिट में एक सौ विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक सेवा से जुडत्री गतिविधियों के संचालन के लिए विभिन्न अवधि के शिविर का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी महाविद्यालयों को मिलाकर राष्ट्रीय सेवा योजना की कुल 8 युनिट हैं, जिसमें 653 विद्यार्थी सेवारत हैं। कुंभलगढ़, देवगढ़ और रेलमगरा महाविद्यालय में एन.एस.एस. की अभी कोई युनिट नहीं है।

5. राष्ट्रीय केडिट कोर (एन.सी.सी.)–'एकता और अनुशासन' की थीम पर आधारित यह योजना कॉलेज और विश्वविद्यालयों में संचालित है। आपात स्थिति में रक्षा सेवाओं के सहायक के रूप में एन.सी.सी. कैडेट्स को तैयार किया जाता रहा है। जिले में केवल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नाथद्वारा में एन.सी.सी. संचालित है। नोडल कॉलेज राजसमंद में भी एन.सी.सी का नहीं होना चिंताजनक है। यहाँ छात्र–छात्राओं में रक्षा सेवाओं के लिए गहरी दिलचस्पी है। ऐसे में सभी महाविद्यालयों में एन.सी.सी. का होना बहुत जरूरी है।
6. विभिन्न छात्रवृत्तियाँ–कॉलेज शिक्षा के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को अलग–अलग विभागों द्वारा छात्रवृत्तियाँ वितरित की जा रही हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति देता है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिक्ख और पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को वजीफा देता है। जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग भी जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यमों से आर्थिक सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। कॉलेज शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत् दो लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों से आने वाले वरीयता प्राप्त एक लाख विद्यार्थियों को पाँ हजार रूपये प्रतिवर्ष दिया जा रहा हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत् कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतिवर्ष सरकारी कॉलेज में अध्ययनरत् सात हजार छात्राओं को वरीयता के आधार पर निःशुल्क स्कूटी वितरा करता है। विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को देवनाराया छात्रा स्कूटी योजना के तहत् लाभान्वित किया जा रहा है।
7. संवाद संगाम कार्यक्रम–शिक्षक–अभिभावक मुलाकात को ही संवाद संगम कार्यक्रम नाम दिया गया है। हर महीने महाविद्यालय प्रशासन शिक्षक–अभिभावक मिटिंग का आयोजन करता है। इस मिटिंग का उद्देश्य शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना तो है ही, साथ में भामाशाह के रूप में अभिभावक के रूप में अभिभावकों का आर्थिक सहयोग भी महाविद्यालय तक पहुँचना है। संवाद संगाम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के स्तर पर दिक्कते आ रही हैं। मिटिंग में अभिभावकों की उपस्थिति 10 प्रतिशत भी नही हो पा रही है।

छात्र राजनीति और उसकी प्रभावशीलता

उच्च शिक्षा में छात्र राजनीति की उपादेयता एक विमर्श का विषय रही है। अध्ययन में 74 प्रतिशत विद्यार्थियों ने माना की छात्रसंघ चुनाव से कॉलेज परिसर का माहौल खराब हुआ है और शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। छब्बीस प्रतिशत विद्यार्थी छात्र राजनीति को उपयोगी और राजनीतिक प्रशिक्षाकी पहली पाठशाला मानते हैं। लिंगदोह समिति की सिफारिश के बाद छात्रसंघ चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रवेश को निषिद्ध किया गया, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से आज भी राजनीतिक दल छात्रसंघ चुनाव में अपना दखल दे रहे हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

महत्त्वपूर्ण बात कॉलेज शिक्षा के हालात को संवारने की है, ताकि गुणात्मक उच्च शिक्षा के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। खस्ताहाल महाविद्यालयों के सहारे हम विश्वगुरू नहीं बन सकते। यद्यपि हमारे अध्ययन का दायरा राजसमंद जिला है, किंतु राज्य के अधिकांश महाविद्यालय लगभग साझी समस्याओं से जूझ रहे है। इसलिए सुधार का जो रोडमैप हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसका सीधा संबंध राजसमंद जिले की कॉलेज शिक्षा से तो है ही, साथ में इसके दायरे में सम्पूर्ण राज्य की कॉलेज शिक्षा को भी समझा जा सकता है।

- प्राचार्य, टिचिंग स्टॉफ, मंत्रालयी स्टॉफ, पुस्तकालय स्टाफ और शारीरिक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करनी होगी, ताकि जिले के सभी महाविद्यालयों में मानवीय संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति की जा सके। प्राचार्य के अभाव में महाविद्यालयों में महत्त्वपूर्ण निर्णय बकाया चल रहे हैं। टिचिंग स्टॉफ के अभाव में प्रभावी शिक्षण व्यवस्था नहीं बन पा रही है। मंत्रालयी कार्मिकों के अभाव में टिचिंग स्टॉफ को कार्यालय संभावना पड़ रहा है।
- संकाय विकास की दिशा में पर्याप्त धन देने की जरूरत है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे परिवर्तनों के अनुरूप हमें कॉलेज शिक्षकों को तैयार करना होगा। अध्ययन में सामने आया है कि जिले के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से पचास प्रतिशत से अधिक शिक्षकों ने पीएच.डी. ही नहीं किया है। रिसर्च के क्षेत्र में शिक्षकों का रूझान उल्लेखनीय नहीं है। यद्यपि कॉलेज शिक्षा विभाग फैकल्टी डवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा शिक्षकों में रिसर्च और तकनीक उन्नयन का प्रयास कर रहा है, किंतु इस प्रयास को अधिक विस्तृत और लक्षित करना होगा।
- ऑनलाईन टिचिंग समय की जरूरत है। अतः शिक्षक, विद्यार्थी और कॉलेज परिसर को डिजिटल सुविधाओं से युक्त करना होगा। महाविद्यालय में वर्चुअल लैब, डिजिटिल लाइब्रेरी, वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था करनी होगी। दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए विशेष डिजिटल उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी।
- शिक्षकों का संतुलित नियोजन करना होगा। अभी भी शहरी महाविद्यालयों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं वहीं ग्रामीण महाविद्यालय टिचिंग स्टॉफ के अभाव का सामना कर रहे हैं। इसी तरह का असंतुलन संभागवार भी दिखता है। जयपुर और भरतपुर संभाग में कॉलेज शिक्षकों का नियोजन शेष संभागों की तुलना में कहीं अधिक है। सॉफ्टवेयर आधारित स्थानान्तरण नीति से इस असंतुलन को दूर किया जा सकता है।
- उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में केवल बदलाव किया जाना ही काफी नहीं है अपितु बदलाव समय सापेक्ष भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए, जिससे उच्च शिक्षा कौशल और व्यावसायिक विकास के साथ एकीकृत हो सके। नई शिक्षा नीति–2020 में भी उच्च शिक्षा को कौशल विकास के साथ जोड़ने पर बल दिया गया है।
- सभी महाविद्यालयों को शुद्ध पेयजल और शौचालय की व्यवस्था तय मानकों के अनुसार करनी होगी। शौचालय की नियमित साफ–सफाई भी बहुत जरूरी है। पर्यावरण स्वच्छता और ग्रीन कैम्पस के लिए

नवाचारों पर काम करना होगा। महाविद्यालय के भौतिक विकास में भामाशाहों के सहयोग को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

- सभी महाविद्यालयों को शुद्ध पेयजल और शौचालय की व्यवस्था तय मानकों के अनुसार करनी होगी। शौचालय की नियमित साफ–सफाई भी बहुत जरूरी है। पर्यावरण स्वच्छता और ग्रीन कैम्पस के लिए नवाचारों पर काम करना होगा। महाविद्यालय के भौतिक विकास में भामाशाहों के सहयोग को भी आमंत्रित किया जा सकता है।
- छात्र राजनीति में व्याप्त दुर्बलताओं के निराकरण हेतु लिंगदोह समिति की सिफारिशों को प्रमुखता से लागू करना होगा। अभी भी छात्रसंघ चुनाव में वित्तीय सीमाओं और दलीय दूरी का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है।

प्रत्येक शोधकर्ता की समझ या विश्लेषण का अपना एक दायरा होता है। अतः हम यह दावा तो नहीं कर सकते कि हमने सुधारों की जो योजना दी है वह अंतिम या सर्वोतम है। अनुसंधान की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहती है, किंतु उपर्युक्त सुझावों को अमल में लाकर कॉलेज शिक्षा में बहुत हद तक गुणात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि शोधकर्ता और नीति निर्माताओं के लिए यह शोध–पत्र उपयोगी साबित होगा।